बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 223 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 05 सितम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

विदेशी आरोपी ने ली बेल और फिर हो गया फरार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नीति बनाने के दिए निर्देश

नई दिल्ली ।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भारत में अपराध के आरोपी विदेशी नागरिकों को देश से भागने से रोकने के लिए एक उपयुक्त नीति बनाने पर विचार करने को कहा है। यह मुद्दा तब उठा जब एक हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामले में आरोपी एक नाइजीरियाई नागरिक, मई 2022 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद कथित तौर पर अपने देश भाग गया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में जमानत आदेश को रद्द कर दिया था और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस लाया जाए। साथ ही, इसने कुछ और करने की आवश्यकता को रेखांकित किया... क्योंकि ऐसे मामले सामने आते रहते हैं,

शिक्षक राष्ट्र के असली निर्माता: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा

मंत्री ने निजी कोश से 5 लाख का अनुदान देने की की घोषणा कैबिनेट मंत्री ने नेशनल टीचर डे पर सैकड़ो अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित थिराना के प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर में हुआ नेशनल टीचर डे सम्मान समारोह

पानीपत।

हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि शिक्षक समाज की नींव होते हैं। वे केवल पढ़ाई ही नहीं कराते बल्कि अच्छे संस्कार, जीवन मूल्य और सही दिशा भी देते हैं। शिक्षक राष्ट्र के असली निर्माता होते है। शिक्षक दिवस का उद्देश्य शिक्षा के महत्व को रेखांकित करना और समाज में शिक्षक की भूमिका को सम्मानित करना है। यह दिन यह संदेश देता है कि शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाते हैं। वे गुरुवार को ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के थिराना स्थित दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस सभागार में आयोजित जिला स्तरीय नेशनल टीचर डे कार्यक्रम के अवसर पर जिले भर के टीचरों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सैकड़ो अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर संस्था के पदाधिकारी ने बुके देकर मंत्री का अभिनंदन किया। मंत्री ने कहा कि इस दिन टीचर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन हैं और यह संकल्प लेने का भी दिन हैं कि शिक्षक का सम्मान

हर दिन होना चाहिए, क्योंकि वही असली राष्ट्र निर्माता हैं। मंत्री ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने संस्थान को अपनी निजी कोष से 5 लाख का अनुदान देने की घोषणा की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शिक्षा के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए संस्कारों का होना अति आवश्यक है। जो विद्यार्थी संस्कारों के साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे वे निश्चित रूप से अच्छे नागरिक बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह संस्था मानवता की भलाई के लिए देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अहम भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा ने कहा कि अध्यापकों में अनुशासन का होना अति आवश्यक है जो अध्यापक स्वयं अनुशासन का पालन करते हैं व बच्चों को भी अनुशासन का पालन करना सीखते है वे विद्यार्थी और अध्यापक आगे चलकर समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। संस्था की शिक्षा विंग की कोऑर्डिनेटर बी के सुमन ने कहा कि संस्था का बेस पवित्रता और संस्कारों पर टिका हुआ है। संस्था द्वारा स्वच्छता को लेकर राष्टीय स्तर पर अभियान की शुरुआत की गई थी । जिसका प्रभाव देश दुनिया में दिखाई दिया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के भाई

हरपाल ढांडा ने कहा कि सही मायने में शिक्षक ही देश को मजबूती प्रदान करते हैं ।उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे देश को मजबूत बनाते हैं और दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं।

आज देश की गिनती शक्तिशाली देश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा ने कहा कि अच्छे शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह बच्चों को इस तरह से तराशे की वो आने वाले समय में समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। वह समाज को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएं। कार्यक्रम में संस्था के निदेशक भारत भूषण ने बताया कि संस्था द्वारा 23 से 25 अगस्त को देशभर में रक्तदान शिविर लगाए गए जिसमें 88 लाख लोगों ने रक्तदान किया इससे पूर्व 108 स्वास्थ्य मेलो का भी आयोजन किया गया था। उन्होंने संस्था की प्रगति पर प्रकाश डाला। संस्था की संचालिका सरला बहन ने कहा कि श्रेष्ठ जीवन के लिए अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित अध्यापकों को इस अवसर पर मेडिटेशन भी कराया। कार्यक्रम में ब्रह्मानंद स्कूल के बच्चों ने व नागपुर से आई सांस्कृतिक टीम के सदस्यों ने आध्यात्मिक कार्यक्रम में बेहतरीन प्रस्तुति देकर अध्यापकों का मनोरंजन किया। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता साबित पानू, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता कर्ण बहल, बी के. ज्योति, प्रिंसिपल पवन आर्य, पूर्व प्रिंसिपल लालचंद रंगा के अलावा सैकड़ो की संख्या में अध्यापक मौजूद रहे।

टीवी पर ज़्यादा और ज़मीन पर कम... संबित पात्रा का तंज, आम आदमी पार्टी में बदल गई कांग्रेस

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह नई आम आदमी पार्टी बन गई है, जो बिना किसी सबूत के संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जीएसटी सुधारों पर प्रेस वार्ता आयोजित करने और यह बताने को कहा कि इस कदम से किसानों को फायदा हो रहा है या नहीं। पात्रा ने राष्टीय राजधानी में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस पार्टी को आज तस्क्षत्रद्धद्भह्नद्धह्न पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि इससे किसानों और परिवारों को फायदा हुआ है या नहीं? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता।

वे बिना सबूत के कुछ संस्थाओं को गाली देते हैं, बिना तथ्यों के वोट चोरी की बात करते हैं और केवल टेलीविजन पर बोलते हैं। पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी जैसी होती जा रही है, टेलीविजन पर ज़्यादा और ज़मीन पर

कम... कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी में बदल गई है। पात्रा ने आगे कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार न केवल एक बड़ा बदलाव है, बल्कि खुशियों की सौगात भी है। संबित पात्रा ने संवाददाताओं से कहा कि यह सिर्फ़ एक सुधार नहीं है, यह एक बहुत बड़ा बदलाव और खुशियों की सौगात है...मोदी है तो मुमकिन है!...जिन लोगों को यह असंभव लगता था, अब उनके लिए सोचने का समय आ गया है। उन्होंने 2017 में जीएसटी लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सराहना की और कहा कि पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यापार करने में आसानी का एक उदाहरण होगा। छोटे व्यवसायों को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि याद कीजिए, जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। पिछली सरकारें इसे लागू नहीं कर पाईं, लेकिन मोदी सरकार ने इसे लागू किया। आज, कोई भी नया व्यवसाय केवल 3 दिनों में पंजीकृत हो सकता है। यह ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का एक उदाहरण है। इसका सबसे बड़ा लाभ छोटे व्यवसायों को मिला है। उन्होंने जीएसटी सुधारों के कारण ट्रैक्टरों के सस्ते होने का उल्लेख करते हुए कहा कि 75 वर्षों तक ट्रैक्टर का बोझ उठाने वाला किसान अब राहत महसूस करेगा। पात्रा ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार में बच्चे के लिए इनाम की निशानी साइकिल भी जीएसटी सुधारों के बाद सस्ती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 75 सालों तक ट्रैक्टर का बोझ ढोने वाला किसान अब असली राहत महसूस कर रहा है। किसान सालों तक टैक्स का बोझ ढोता रहा, लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आया है जहाँ उसे राहत मिली है। सोचिए, जब गाँव के किसान को लगता है कि ट्रैक्टर सस्ता हो गया है, जब घर का बच्चा खुश होता है कि अब उसे साइकिल मिल सकती है, और जब मध्यम वर्गीय परिवार को लगता है कि उनकी छोटी कार या मोटरसाइकिल अब सस्ती हो गई है - तो उनके जीवन में कितनी खुशियाँ आ जाती हैं।

जीएसटी दरों में कटौती देश के लिए बड़ी सौगात, दिल्ली को फायदा होगा- सीएम

`नई दिल्ली । (वेबवार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती देश के लिए एक बड़ा उपहार है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बुधवार को जीएसटी परिषद की पहली बैठक में शामिल हुईं गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस कदम से देश में व्यापार और कारोबार मजबूत होगा। रेखा गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा, ''यह देश के लिए बहुत बड़ी सौगात है... स्वास्थ्य बीमा और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दरों में कटौती देश के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी की दरों में संशोधन को अपार समर्थन के साथ पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा तथा यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा। गुप्ता ने कहा, '' दिल्ली बहुत खुश है और मैं दिल्लीवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य बीमा तथा शिक्षा संबंधी वस्तुओं पर शून्य जीएसटी लगाने के लिए धन्यवाद देती हूं। नवीकरणीय ऊर्जा को समर्थन दिया गया है और इससे दिल्ली को काफी लाभ होगा क्योंकि हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर में व्यापक सुधारों को मंजूरी दी। इन सुधारों के तहत साबुन, साइकिल, टीवी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पॉलिसी जैसे आम उपयोग के उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम की गयी हैं। जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गयी है। कुछ चुनिंदा वस्तुओं जैसे महंगी कारें, तंबाकू और सिगरेट के लिए भी 40 प्रतिशत का विशेष स्लैब

सीएम रेखा गुप्ता बोलीं, स्थानीय वस्तुओं के महत्व को समझाना शिक्षकों की अहम जिम्मेदारी

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को शिक्षकों से आह्वान किया कि वे स्कूली बचों को केवल शिक्षा तक सीमित न रखकर उन्हें भारतीय संस्कृति, स्वदेशी जीवनशैली और पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ें. उन्होंने कहा कि शिक्षक ही वह मार्गदर्शक शक्ति हैं, जो बचों को आने वाले समय में जिम्मेदार नागरिक और सक्षम नेता बना सकते हैं. रेखा गुप्ता एनडीएमसी की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थीं. पांच सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने कहा कि आज बचों को यह समझाने की जरूरत है कि स्वदेशी का सही अर्थ क्या है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर हम विदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं तो उसका सीधा असर हमारे स्थानीय व्यवसायों और छोटे उद्योगों पर पड़ता है. इसलिए, बचों को स्थानीय वस्तुओं के महत्व को समझाना शिक्षकों की अहम जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्रों को जल संरक्षण, पेड़-पौधों के महत्व, पहाड़ों और नदियों के संरक्षण की शिक्षा दें. इससे बचों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगी और वे पर्यावरण के संरक्षक के रूप में समाज में योगदान कर सकेंगे. रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मौजूदा समस्याओं, विशेषकर यमुना नदी की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि शहर को सुधारने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर यमुना मेरे सामने आए तो मैं उससे माफी मांगूंगी, क्योंकि उसकी गंदगी और प्रदूषण के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं. हमें इसे सुधारने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग अक्सर शहर की समस्याओं के लिए केवल सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हर नागरिक की भूमिका अहम है. यदि हम सब मिलकर छोटे-छोटे कदम उठाएं तो न केवल दिल्ली की स्थिति सुधरेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वच्छ वातावरण भी तैयार होगा. मुख्यमंत्री ने अंत में शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक ही समाज के वास्तविक शिल्पकार हैं. वे बचों को सही दिशा देकर न केवल उनकी व्यक्तिगत जिंदगी को संवारते हैं बल्कि पूरे देश का भविष्य गढ़ते हैं. उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे बचों में स्वदेशी सोच, संस्कृति के प्रति जुड़ाव और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा दें, ताकि भारत के आने वाले नेता संस्कृति और प्रकृति से जुड़े हुए हों.

उम्मीदों की चिप से हौसलों की उड़ान भरता भारत

ललित गर्ग ।

भारत ने तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया इतिहास रचते हुए अपना पहला पूर्णतया स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर तैयार कर एक तकनीकी क्रांति को आकार दिया है। यह उपलब्धि न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। भारत ने इस तकनीकी क्रांति की तरफ कदम बढ़ते हुए आत्मनिर्भर एवं स्वदेशी तकनीकी प्रगति को नये आयाम दिये है। पहला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित करने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिये इसरो की सेमीकंडक्टर लैब साक्षी बनी है। पहली मेड इन इंडिया चिप का उत्पादन गुजरात के साणंद स्थित पायलट प्लांट में शुरू होगा। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत 18 अरब डॉलर से ज्यादा के कुल निवेश वाली दस सेमीकंडक्टर परियोजनाएं देश में चल रही है, अब भारत को इस तरह की तकनीक के लिये विदेशों के पराधीन नहीं होना होगा। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले चिप क्षेत्र में भारत की यह दस्तक उत्साह जगाने वाली है, निश्चित ही इससे भारत की ताकत बढ़ेगी और तकनीक के साथ-साथ यह आर्थिक विकास को तीव्र गति देगा। फिलहाल आधुनिक समय की इस जादुई चिप के उत्पादन में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों का वर्चस्व है। विशेषतः भारत की यह जादुई उपलब्धि अमेरिका को आइना दिखाने वाली है, ट्रंप को यह एक बड़ा झटका है। भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिये उत्सुक है। तभी सेमीकॉन इंडिया-2025 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में बड़े बदलाव की नींव रखेगी। हालांकि, इस राह में अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है कि छह सौ अरब डॉलर वाले वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर की हो सकती है, जिससे भारत अनेक मोर्चों पर सफलता के परचम फहरायेगा। इस स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अर्धचालक प्रयोगशाला ने अभिकल्पित किया है और इसे विक्रम नाम दिया गया है। यह अंतरिक्ष-मानक माइक्रोप्रोसेसर है, जो मुख्यतः अंतरिक्ष अभियानों और रॉकेट प्रणालियों में प्रयोग के लिए तैयार किया गया है। इसरो ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) चंडीगढ़ के साथ मिलकर दो स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए है। यह माइक्रोप्रोसेसर प्रक्षेपण यानों के नेविगेशन और नियंत्रण में मदद करेंगे। विक्रम 3201 पूरी तरह भारत में बना पहला 32-बिट प्रोसेसर है। इस कदम से इसरो को विदेशी प्रोसेसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जिससे अंतरिक्ष में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। निश्चित ही इससे भारत ने महाशक्ति बनने की ओर अपनी गति को तीव्रता दी है, जिससे अमेरिका हिला और दुनिया भारत की ताकत से रू-ब-रू हो रही है। अब तक भारत को अनेक जटिल अंतरिक्ष अभियानों के संचालन हेतु विदेशी सूक्ष्म-प्रक्रमकों और अर्धचालक पट्टिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। यह विदेशी निर्भरता न केवल आर्थिक दृष्टि से बोझिल थी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण थी। विक्रम माइक्रोप्रोसेसर के निर्माण से भारत ने इस निर्भरता की बेड़ियों को तोड़ा है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त कदम बढ़ाया है। निस्संदेह, भारत को चिप उत्पादन क्षेत्र में एक दिग्गज देश बनने के लिए निरंतर निवेश, अनुसंधान-विकास और विनिर्माण की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिये निरन्तर प्रयासरत है। हाल ही में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से उम्मीद जगी है कि वह वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करने में भारत के लिये मददगार साबित हो सकता है। यह सुखद ही है कि भारत में चिप उत्पादन परियोजनाओं में जापानी निवेश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं भारत को ऐसे ही विकास के नये शिखरों पर आरोहण कराने का सशक्त माध्यम बन रही है। निश्चित रूप से मोदी सरकार के प्रयासों से भारत चिप उत्पादन के वैश्विक महत्वाकांक्षी अभियान की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ सकता है। दरअसल, डिजिटल डिवाइसों का मस्तिष्क कहा जाने वाला सेमीकंडक्टर कंप्यूटर, मोबाइल, राउटर, कार, सैटलाइट जैसे उन्नत डिजिटल डिवाइस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन उपकरणों की कार्यकुशलता उन्नत चिप की ताकत पर निर्भर करती है। साधारण शब्दों में कहें चिप पतली सिलिकॉन वेफर पर बने लाखों-करोड़ों ट्रांजिस्टरों का संजाल है। जो कंप्यूट करने, मेमोरी प्रबंधन व सिग्नल प्रोसेस करके डिवाइस को उन्नत बनाती है। उम्मीद है कि भारत का स्वदेशी चिप इस साल के आखिर तक बाजार में आ सकेगी। जिसका असर जियोपॉलिटिक्स पर तो होगा ही, नये रोजगार सृजन का वातावरण भी बनेगा, भारत तकनीकी विकास के नये आयाम उद्घाटित करते हुए विश्व को अचंभित भी करेगा। निश्चय ही भारत यदि अनुसंधान-विकास व व्यापार सुगमता की स्थितियां निर्मित कर लेता है तो हमारी सेमीकंडक्टर आयात के लिये दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे हम वैश्विक दबाव से मुक्त होकर अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बना सकते हैं। 32-बिट क्षमता का अर्थ है कि यह माइक्रोप्रोसेसर अधिक व्यापक स्मृति का उपयोग कर सकता है और जटिल संगणकीय कार्यों को तीव्र गति से संपन्न कर सकता है। अंतरिक्ष अभियानों में जहाँ प्रत्येक क्षण और प्रत्येक संकेत का महत्व होता है, वहाँ इस प्रकार की क्षमता अत्यंत आवश्यक है। यह केवल गति और कार्यकुशलता नहीं देता बल्कि विकिरण-सहनशीलता और दीर्घकालीन स्थिरता जैसे गुण भी समाहित करता है। अंतरिक्ष में प्रबल विकिरण, तापमान का उतार-चढ़ाव और कठोर परिस्थितियाँ होती हैं, जिनका सामना सामान्य माइक्रोप्रोसेसर नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार का अंतरिक्ष-योग्य माइक्रोप्रोसेसर ही मिशनों की सफलता का आधार बन सकता है। इस उपलब्धि का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके लिए आवश्यक रूपांकन, निर्माण और परीक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया भारत में ही सम्पन्न की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत अब केवल प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं बल्कि उसका सर्जक भी है। सूक्ष्म-संगणक की यह अभिकल्पना केवल एक चिप का निर्माण नहीं है, यह भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा, उसकी दूरदृष्टि और आत्मविश्वास का परिचायक है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सफलता हासिल करने की दिशा में भारत का एक सशक्त पक्ष यह भी है कि दुनिया के लगभग बीस फीसदी चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में है। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी क्षेत्र में कामयाबी के लिये भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सरकार बड़ी घरेलू कंपनियों को संबल देने के लिये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई के तहत दिए जा रहे लाभ के विस्तार के साथ ही, इसके तहत दिये जाने वाले अनुदान को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जिसके तहत महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादन परियोजनाओं के लिये केंद्र व राज्यों से प्रोत्साहन के रूप में परियोजना की कुल लागत का सत्तर फीसदी मिलना जारी रह सकता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में गेम चेंजर टेक क्रांति माना जा रहा है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थान पहले ही शक्ति और वेगा जैसे स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर पर काम कर चुके है। इन प्रयासों ने आधारभूमि तैयार की और आज विक्रम के रूप में वह प्रयास मूर्त रूप में सामने आया है। यह न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र बल्कि रक्षा, चिकित्सा उपकरणों और संचार प्रणाली में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। निश्चित ही चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन, उपकरण-समूह की उपलब्धता, संगणक-कार्यक्रमों का विकास, अनुप्रयोग-तंत्र का विस्तार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणन जैसी प्रक्रियाएँ अभी पूरी करनी होंगी। किंतु भारत ने जिस आत्मविश्वास के साथ इस दिशा में पहला कदम रखा है, वह आश्वस्त करता है कि भविष्य में हम और भी उन्नत सूक्ष्म-प्रक्रमक तैयार करने में सक्षम होंगे। विक्रम केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारत की स्वाभिमानी यात्रा का घोष है। यह घोषणा है कि अब भारत केवल विज्ञान का अनुयायी नहीं बल्कि विज्ञान का निर्माता और मार्गदर्शक बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना अब शब्दों में नहीं, ठोस उपलब्धियों में आकार ले रही है।

सम्पादकीय...

मनीषा की हत्या......

हरियाणा के भिवानी की शिक्षिका मनीषा की हत्या ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया है, बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। यह घटना फिर से उस गहरे सवाल को सामने लाती है जो वर्षों से हमारे न्याय तंत्र पर मंडराता आ रहा है, क्या हमारे देश में समय पर न्याय मिल पाना संभव है? मनीषा का मामला अब सीबीआई के पास भेजने की प्रक्रिया में है। पुलिस ने मुख्यालय को पत्र लिख दिया है और उम्मीद जगाई जा रही है कि सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्या यह मान लेना चाहिए कि सीबीआई जांच ही न्याय की गारंटी है? अतीत के कई मामलों को देखें तो जवाब निराशाजनक मिलता है। हरियाणा और आसपास के जिलों के कई ऐसे बड़े केस हैं जिन्हें सालों पहले सीबीआई को सौंपा गया लेकिन आज भी वे न्याय की मंज़िल तक नहीं पहुंचे। 1995 में 11वीं कक्षा की छात्रा की हत्या हुई थी, आरोपी 30 साल से फरार है। यह केवल पीड़िता के परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल है। 2013 में पूर्व जज द्वारा पत्नी की हत्या का मामला पिछले 12 साल से कोर्ट में लंबित है। आरोपी को 2016 में गिरफ्तार किया गया लेकिन ट्रायल आज भी अधूरा है। 2017 में छात्र की हत्या के मामले में सीबीआई ने स्कूल के ही छात्र को आरोपी बनाया था। पर केस का कोई अंतिम नतीजा सामने नहीं आया। 2022 का सोनाली हत्याकांड भी तीन साल बाद अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि हत्या क्यों हुई। इसी तरह प्रेम विवाह पर युवक की हत्या का केस 2015 से कोर्ट में चल रहा है और आठ साल बाद भी फैसला नहीं आया। इन उदाहरणों से साफ है कि सीबीआई को केस सौंप देना न्याय का पर्याय नहीं है। कई बार तो यह केसों को और ज्यादा लंबा कर देता है। न्याय में देरी केवल कानूनी औपचारिकता नहीं है, यह सीधे-सीधे पीड़ित परिवार पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक बोझ डालती है। हर सुनवाई पर परिवार के सदस्य उम्मीद लेकर कोर्ट जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज कोई ठोस कदम उठेगा। लेकिन बार-बार अगली तारीख मिलती है। यह सिलसिला महीनों नहीं, बल्कि वर्षों तक चलता रहता है। ऐसे में पीड़ित परिवार की हिम्मत टूट जाती है। कई बार गवाह समय के साथ कमजोर हो जाते हैं या डर के कारण पलट जाते हैं। सबूत समय बीतने के साथ कमजोर पड़ जाते हैं। आरोपी खुलेआम समाज में घूमते रहते हैं और पीड़ित परिवार यह सोचता रह जाता है कि कानून आखिर किसके लिए बना है। देरी की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की जिम्मेदारी है कि फरार आरोपियों को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करे लेकिन कई मामलों में आरोपी वर्षों तक फरार रहते हैं और पुलिस केवल बयान देती रह जाती है। सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां अक्सर केस की जांच लंबी खींच देती हैं। रिपोर्ट्स तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं और कभी-कभी राजनीतिक दबाव भी जांच की दिशा बदल देता है। न्यायपालिका में केसों की संख्या इतनी अधिक है कि हर सुनवाई महीनों बाद मिलती है। ट्रायल की प्रक्रिया धीमी है और फैसला आने में दशकों लग जाते हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर न्यायिक ढांचे को पर्याप्त संसाधन और आधुनिक तकनीक नहीं दी जाएगी तो देरी होना तय है। जब अपराधी खुले घूमते हैं और पीड़ित परिवार अदालतों के चक्कर लगाता रहता है, तो समाज का भरोसा कानून से उठने लगता है। लोग धीरे-धीरे यह सोचने लगते हैं कि न्याय मिल ही नहीं सकता। अगर हम वास्तव में यह चाहते हैं कि मनीषा और उसके जैसी बेटियों को न्याय मिले, तो इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जघन्य अपराधों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं ताकि सुनवाई समयबद्ध हो। सीबीआई जांच के लिए समय सीमा तय की जाए। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए। हर छह महीने में पीड़ित परिवार को केस की स्थिति बताई जाए। अदालतों और जांच एजेंसियों में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हो ताकि देरी का कारण साफ़ दिखाई दे। गवाह संरक्षण योजना को सख्ती से लागू किया जाए ताकि गवाह डर के कारण पलट न सकें। मनीषा की हत्या कोई साधारण अपराध नहीं है। यह हमारे समाज की उस विफलता की कहानी है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और अगर उनके साथ कुछ हो भी जाए तो न्याय पाने में वर्षों लग जाते हैं। मनीषा का परिवार आज भी उम्मीद लगाए बैठा है। अगर यह भी अन्य मामलों की तरह वर्षों तक खिंच गया तो समाज का भरोसा और कमजोर होगा। न्याय में देरी का मतलब है न्याय से इनकार। जब आरोपी सालों तक सज़ा से बच जाते हैं, तो यह संदेश जाता है कि कानून शक्तिशाली के लिए ढीला और कमजोर के लिए सख्त है। मनीषा और उससे पहले की कई बेटियां आज भी इंसाफ़ की आस लगाए बैठी हैं। उनकी आंखों से टपकता दर्द हम सबकी सामूहिक नाकामी है। अब समय आ गया है कि सरकार, न्यायपालिका सुनिश्चित करें कि न्याय समय पर मिलेगा।

तबाही के बाद भी पंजाबियों के हौसले बुलंद

असल में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के मेन हॉल सहित समूचे परिसर में पानी जमा हो गया था और पानी निकलने के बाद जमा गार की सफाई पाकिस्तान प्रशासन के द्वारा की गई जिसे लेकर सिख संगत में काफी रोष देखा जा रहा है। संगत का मानना है कि अगर संगत को वहां जाने की मंजूरी होती तो संगत द्वारा स्वयं इस सेवा को मर्यादा पूर्वक निभाया जाता। इसी के चलते श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार एवं नए बने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह के द्वारा देश की मोदी सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द करतार पुर कोरीडोर को संगत के लिए खोला जाना चाहिए। असल में सिख संगत में रोष इसलिए भी है कि एक ओर संगत को दर्शनों से वंचित रखा जा रहा है वहीं क्रिकेट सहित अन्य खेलों के लिए दोनों देशों में सहमति बनी हुई है, इसलिए अब संगत चाहती है कि बिना देरी के कोरीडोर खोला जाए ताकि जो संगत अभी भी दर्शन नहीं कर सकी वह दर्शन कर पाए।

पंजाब इस समय कुदरती आपदा का शिकार हो चुका है और पंजाब के ज्यादातर गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खेती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। लोगों के मकान, दुकानें, सामान यहां तक कि पशु भी ज्यादातर पानी में बह चुके हैं या फिर मर गए हैं। बावजूद इसके पंजाबियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद देखे जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1947 में देश के बंटवारे में अगर किसी को जान-माल का नुकसान हुआ तो वह पंजाब के लोग ही थे मगर कुछ ही सालों में अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम से उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि समूचे देश में सबसे अधिक अनाज की पैदावार पंजाब में होने लगी। 80 के दशक में पंजाब ने काला दौर देखा जिसने पंजाब की युवा पीढ़ी को खेती से दूर कर विदेश भागने के चलन को जन्म दिया। देश के किसी भी राज्य में किसी तरह की आपदा आई तो पंजाबियों ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। कोरोना काल में तो पंजाबियों ने अपनी सांसों तक के लंगर लगा दिए, पर अफसोस कि आज पंजाब पर आपदा आई तो कोई और राज्य मदद करने के लिए नहीं आया। पंजाब की मदद स्वयं पंजाबियों के द्वारा की जा रही है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, शिरोमणि कमेटी, तख्त पटना साहिब, तख्त हजूर साहिब, मुम्बई से शिरोमणि कमेटी सहित कई बड़ी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े गुरविन्दर सिंह बावा के द्वारा हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। शहीद भगत सिंह सेवादल के जतिन्दर सिंह शन्टी द्वारा एम्बुलेंस भेजी गई है ताकि मेडिकल सेवा में किसी प्रकार दिक्कत ना हो। पंजाबी गायक, कलाकार भी मददगार बनकर सामने आ चुके हैं यहां तक कि विदेशों में बैठे ज्यादातर भारतीय जिनके दिलों में आज भी पंजाब बसता है वह अपना काम-धन्धा छोड़कर अपने पंजाब को पुनः खुशहाल बनाने के लिए पहुंचने लगे हैं। सिखों को भारत के सिवाए और किसी मुल्क में आजादी नहीं - सिख समुदाय को जितनी आजादी भारत में मिली है शायद संसार के किसी और मुल्क में नहीं मिल सकती।

भारत में सिख समुदाय के लोग गुरु साहिबान द्वारा दी गई मर्यादा, परंपरा के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। सिखों के पांच ककारों में से एक कृपाण के संग कहीं भी आ- जा सकते हैं, यहां तक कि संसद और अति संवेदनशील जगहों पर भी सिख कृपाण के साथ प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान सिखों को कृपाण रखने की अनुमति देता है। वहीं दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। भारत के भीतर हवाई जहाज में भी सिख कृपाण पहनकर यात्रा कर सकते हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करते समय कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं मिलती। गुरुद्वारों या नगर कीर्तनों सिख समुदाय कृपाण के संग गतका के प्रदर्शन करते हैं और अब तो गतका को ओलंपिक खेलों में भी स्थान दिया गया है मगर विदेशों में कृपाण लेकर चलने की आजादी नहीं है जिसका ताजा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब अमेरिका के लॉस एंजेलस में एक शख्स ने अचानक अपनी कार बीच सड़क पर रोक दी और और 'गतका' (सिखों की पारंपरिक युद्धकला) करने लगा। घटना उस स्थान के पास हुई, जहां अक्सर भीड़ रहती है। वहां मौजूद लोग डर गए और तुरंत पुलिस को कॉल किया। मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने बार-बार उस शख्स से कृपाण नीचे रखने को कहा लेकिन वह लगातार कृपाण घुमाता रहा और कभी पुलिस की तरफ तो कभी राह चलते वाहनों की ओर बढ़ने लगा जिसके बाद पुलिस ने उस सिख युवक पर अनगिनत कई गोलियां चला दी जिससे उसकी मौत हो गई। भारत में आज तक किसी सिख के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ फिर भी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी प्रवृति के लोग भारत में सिखों को गुलाम बताते हैं जबकि देखा जाए तो भारत के सिवाए और किसी भी देश में सिखों को अपने धार्मिक चिन्हों के साथ जीवन व्यतीत करने की आजादी हासिल नहीं है। कैनेडा के हिन्दू सिखों को खालिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाने की आवश्यकता - आज से 40 साल पहले कैनेडा की धरती पर बैठकर खालिस्तानियों के द्वारा बम तैयार किया गया और उसी बम से कैनेडा से भारत आने वाले एयर इन्डिया के एक जहाज को हवा में ही बम से उड़ा दिया जिसमें 329 यात्री मारे गए जिनमें 82 मासूम बच्चे भी थे। उसी समय, टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर एक और बम विस्फोट हुआ जो एयर इंडिया की एक अन्य उड़ान ए आई-301 के लिए था। यह बम चढ़ाए जाने से पहले ही फट गया, जिसमें दो जापानी बैगेज हैंडलर्स की मौत हो गई। मगर ऐसा लगता है कि कैनेडा के लोगों ने 40 साल पूर्व हुई इस घटना से अब तक कोई सबक नहीं लिया जिसके चलते आज भी खालिस्तानी खुलेआम अपनी गतिविधियों को अन्जाम देते आ रहे हैं। इस घटना के मास्टर माईंड को उल्टा एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है फिर भी ना जाने क्यों कैनेडा की सरकार इन लोगों के खिलाफ आज तक कार्रवाई करना तो दूर उल्टा उन्हें प्रोत्साहन देती आ रही है जिसके परिणाम स्वरूप खालिस्तानियों के हौसले बुलंद है और वह खुलकर भारत के खिलाफ गतिविधियों को अन्जाम देते हैं। कनिष्क बम काण्ड में अपना पूरा परिवार खो चुके संजय लाजार नामक शख्स ने जिसकी उम्र उस समय मात्र 17 साल की थी और आज 57 साल का हो चुका है। कैनेडा में रहते हिन्दू-सिख भाईचारे के लोगों से अपील की है कि इन 329 लोगों को श्रद्धांजलि यही होगी कि खुलकर खालिस्तानियों का विरोध करने के लिए आगे आएं जिससे सरकार को भी यह समझ आ जाए कि कोई भी सिख भले ही संसार के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो ना तो कभी खालिस्तानी समर्थक था और ना हो सकता है। इस हादसे का जिक्र करते हुए तख्त पटना साहिब के प्रवक्ता हरपाल सिंह जौहल का कहना है कि हमें तो आज तक यह समझ नहीं आ रहा कि खालिस्तानी असल में क्या चाहते हैं क्योंकि एक ओर वह सिख समाज के लोगों के लिए अलग देश की मांग करते हैं और दूसरी ओर सिखों पर ही अत्याचार करते हैं, क्योंकि कनिष्क हवाई हादसे में भी मरने वाले ज्यादातर सिख समाज के ही लोग थे जिससे एक बात संसार भर के सिखों को समझ लेनी चाहिए कि खालिस्तानी समर्थकों का मकसद पाकिस्तान के इशारे पर भारत में आतंक का माहौल बनाने से अधिक और कुछ नहीं है। करतारपुर कोरीडोर खोलने की उठी मांग -बीते समय में जंग के ऐलान के बीच करतारपुर कोरीडोर को सरकार ने पुनः बन्द कर दिया था जिसे खोलने की मांग अब फिर से उठने लगी है। असल में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के मेन हॉल सहित समूचे परिसर में पानी जमा हो गया था और पानी निकलने के बाद जमा गार की सफाई पाकिस्तान प्रशासन के द्वारा की गई जिसे लेकर सिख संगत में काफी रोष देखा जा रहा है। संगत का मानना है कि अगर संगत को वहां जाने की मंजूरी होती तो संगत द्वारा स्वयं इस सेवा को मर्यादा पूर्वक निभाया जाता। इसी के चलते श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार एवं नए बने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह के द्वारा देश की मोदी सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द करतार पुर कोरीडोर को संगत के लिए खोला जाना चाहिए। असल में सिख संगत में रोष इसलिए भी है कि एक ओर संगत को दर्शनों से वंचित रखा जा रहा है वहीं क्रिकेट सहित अन्य खेलों के लिए दोनों देशों में सहमति बनी हुई है, इसलिए अब संगत चाहती है कि बिना देरी के कोरीडोर खोला जाए ताकि जो संगत अभी भी दर्शन नहीं कर सकी वह दर्शन कर पाए।

राजनीति में लोकलज्जा

राजनीति में गाली-गलौच के लिए कोई स्थान नहीं होता क्योंकि इसकी मार्फत लोकतन्त्र में आम जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। यह लड़ाई पूर्णतः वैचारिक आधार पर होती है अतः जब भी राजनीति में भाषा का स्तर गाली पर उतर आता है तो उसे वैचारिक खोखलेपन का सबूत माना जाता है। वैचारिक खोखलापन राजनीति में तब भी माना जाता है जब नीतिगत सिद्धान्तों के स्थान पर व्यक्तिगत आलोचना होने लगती है। प्रख्यात समाजवादी चिन्तक डॉ. राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में जब वैचारिक स्तर पर खोखलापन शुरू होता है तो व्यक्तिगत आलोचना शुरू होती है और यह चरित्र हत्या तक पहुंच जाती है। मगर भारत में पिछले दो दशक से राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है जिसके लिए सत्ता व विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार हैं। हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस प्रकार प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी को मां की गाली दी गई, उसकी हर हाल में हर पक्ष द्वारा निन्दा की जानी चाहिए। सवाल यह नहीं है कि यह गाली एक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा दी गई, बल्कि असल सवाल यह है कि यह गाली कांग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल के मंच से दी गई। यह भी सवाल नहीं है कि उस समय मंच पर कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी व राजद नेता श्री तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे और उनकी सभा समाप्त हो चुकी थी, बल्कि सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने प्रधानमन्त्री को गाली दी उसने इन दोनों नेताओं के मंच का ही प्रयोग किया। अतः बहुत स्वाभाविक सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी सभा के आयोजनकर्ता को लेनी चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि बिहार के दरभंगा शहर में जहां यह घटना घटी वहां के सभा आयोजक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने घटना के लिए माफी मांग ली है जिसके बाद विवाद समाप्त हो जाना चाहिए था, मगर घटना के लिए यदि कांग्रेस व राजद का शीर्ष नेतृत्व भी दुख प्रकट कर देता है तो उससे उसका कद छोटा नहीं हो जायेगा। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है और इसकी विरासत बहुत विशाल व गरिमामयी है। महात्मा गांधी ने 1920 में अपना असहयोग आन्दोलन इसीलिए वापस ले लिया था कि चौरी-चौरा में हिंसक घटना हो गई थी और आन्दोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। अपने आन्दोलन में हिंसा को होते देख राष्ट्रपिता ने आन्दोलन की वापसी की घोषणा कर दी थी। अतः कांग्रेस पार्टी को दरभंगा के मामले पर गंभीरता और गहराई से विचार करने के बाद ही प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी और राजद की यात्रा आम जनता के हकों के लिए ही हो रही थी इसलिए इन दोनों पार्टियों को आम जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए था। इस यात्रा के दौरान गाली जैसी विसंगति के पैदा होने के बाद इस मुद्दे की गंभीरता पर विचार करना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि उनका मुकाबला उस भाजपा पार्टी है से है जो ऐसे मुद्दों को अपने पक्ष में भुनाने की माहिर मानी जाती है। विचारणीय पक्ष यह है कि स्वतन्त्र भारत में भाजपा की राजनीति पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को खामियों पर ही टिकी हुई है। इसके वैचारिक पक्ष का प्रमुख हिस्सा कांग्रेस की आलोचना ही रहा है अतः विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस को हर कदम फूंक- फूंक कर रखना होगा और देश की जनता को दिखाना होगा कि उसकी राजनीति केवल भाजपा की आलोचना पर टिकी हुई नहीं है बल्कि वह अपनी मौलिक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। राजनीति में व्यंग्य-विनोद के लिए तो पर्याप्त स्थान है मगर गाली जैसी कलुषता के लिए लेशमात्र भी जगह नहीं है। भाजपा को जनता के बीच स्थापित करने में इसके स्वर्गीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी का विशिष्ट स्थान माना जाता है। 1969 में जब स्व. वाजपेयी भारतीय जनसंघ (भाजपा) के नये-नये अध्यक्ष बने थे तो उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना अधर में लटक गई थी। इसकी वजह यह थी कि 1962 में भारत की चीन से लड़ाई हुई और 1965 में पाकिस्तान से। इन दोनों लड़ाइयों के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना अधूरी हो रह गई तो स्व. वाजपेयी ने एक जनसभा में कहा कि 'हम सरकार से पूछते हैं कि पंचवर्षीय योजना का क्या हुआ तो वह कहते हैं कि यह प्रसव में है। हम कहते हैं कि जल्दी निकालो तो वे कहते हैं कि पीड़ा होती है'। श्री वाजपेयी के इस कथन को तब विपक्ष की ही स्वतन्त्र पार्टी के नेता स्व. पीलू मोदी ने बहुत गंभीरता से लिया था और कहा था कि श्री वाजपेयी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए क्योंकि उन्होंने नारी की प्रसव वेदना का उपहास उड़ाया है। इस पर वाजपेयी ने दुख भी प्रकट कर दिया था। अतः भारतीय राजनीति की यह परंपरा रही है। ऐसा नहीं है कि दो दशक पहले तक राजनीति पूरी तरह साफ-सुथरी थी। इससे पहले भी सत्ता पक्ष की आलोचना विपक्ष में बैठी पार्टियां जमकर किया करती थीं, खासकर जनसंघ पार्टी तो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी और व्यक्तिगत आलोचना तक पर उतर आती थी मगर उसमें लोकलज्जा का भाव जरूर रहता था। सबसे बड़ी चिन्ता की बात आज यह है कि राजनीति से लोकलज्जा समाप्त होती जा रही है जबकि यह लोकतन्त्र का गहना मानी जाती है। लोकलज्जा को कायम रखना केवल विपक्ष का ही काम नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष की भी यह जिम्मेदारी होती है कि उसका हर काम इसी दायरे में हो। डॉ. लोहिया यह भी कहा करते थे कि लोकतन्त्र केवल लोकलज्जा से ही चल सकता है क्योंकि इसके समाप्त होते ही राजनीतिक द्वेष घृणा का रूप ले लेता है।

मोदी-जिनपिंग भाई, भाई !

जिस प्रकार से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ट्रंप के नहले पर दहला मारा है, वह इस बात की खुली दलील है कि बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पैठ बिठा दी है। दुनिया का ध्यान अब पुतिन, मोदी और जिनपिंग की तिकड़ी पर टिक गया है और अमेरिका परेशान है। इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका की दादागिरी हदें पार कर चुकी थी। हां, पाकिस्तान के आजकल तोते उड़े हुए हैं, कि चीन अब उसके हाथ से निकल सकता है। वैसे भी सी पैक को लेकर चीन और पाकिस्तान में आपस में ठनी हुई है। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ मुलाकात देखकर अमेरिकी सरकार खासा टेंशन में आ गई है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर नई दिल्ली पर हमला बोला है। नवारो ने इस बार चीन के साथ भारत के मेलजोल पर रोना रोया है। यह एक कुदरती बात थी कि तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भेंट दुनिया के लिए एक बड़ा इवेंट था, क्योंकि दोनों सात वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मिले थे। चीन में भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए अमेरिका को जवाब दे दिया। यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। इन तीनों वैश्विक नेताओं की मुलाकात ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी है। इस बीच अब अमेरिका को अपनी गलती का एहसास भी होने लगा है। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की गई है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अब अमेरिका को भारत पर लगाए गए टैरिफ वाली गलती का एहसास हो रहा है और अब अमेरिका अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक रहा। तियानजिन में हुए एससीओ समिट में उन्होंने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया और भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। पीएम मोदी ने पुतिन संग गहन बातचीत कर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि शी जिनपिंग से मुलाकात में ट्रेड और बॉर्डर मुद्दों पर चर्चा की। यह दौरा भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करता दिखा। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी की व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात से अमेरिका की टेंशन साफ दिखने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने इसी लेकर जो बयान दिया है, उससे उनकी बौखलाहट साफ झलकती है। मुलाकात में ट्रेड और बॉर्डर मुद्दों पर चर्चा की। यह दौरा भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करता दिखा। शिखर सम्मेलन ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है। तिआनजिन में आयोजित इस समिट में पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने दुनिया का ध्यान खींचा। तीनों नेताओं की गर्मजोशी और एकजुटता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को करारा जवाब दिया। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने करन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीतमपुरा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

साइबर अपराध पर नकेल कसने को पुलिस कर्मियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण

थाना कनेक्ट सत्र में मिली तकनीकी जानकारी

देवरिया।

साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने और विवेचना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम मुख्यालय के निर्देशन में गुरुवार को थाना कनेक्ट प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस ऑनलाइन सत्र में 14ष्ट के विशेषज्ञ अधिकारियों ने महत्वपूर्ण पोर्टलों के उपयोग, विधिक प्रावधानों और विवेचना की सर्वोत्तम पद्धतियों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। जनपद स्तर पर आयोजित इस सत्र में साइबर नोडल राजपत्रित अधिकारी, साइबर थाना प्रभारी, साइबर सेल प्रभारी, थानों में तैनात विवेचक/कर्मचारी, साइबर हेल्प डेस्क कर्मी तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित विवेचना करने वाले अधिकारीगण शामिल हुए। पुलिस लाइन स्थित सभागार में एकत्र होकर सभी प्रतिभागियों ने ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे तकनीकी उपकरणों और विशेष पोर्टलों का उपयोग कर साइबर अपराधों की रोकथाम और विवेचना को अधिक सटीक बनाया जा सकता है। साथ ही केस स्टडी के माध्यम से अधिकारियों को यह भी सिखाया गया कि किस प्रकार डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना की जाए। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी विनी सिंह, प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना अजय कुमार पांडेय, निरीक्षक राकेश सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर शिवमंगल यादव व आरक्षी विजय कुमार राय सहित विभिन्न थानों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

भरतपुर व ताहिरपुर विद्यालय बने शिक्षा के आदर्श

जौनपुर/सिकरारा।

जनपद के परिषदीय विद्यालय अब शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सिकरारा ब्लॉक का कंपोजिट विद्यालय भरतपुर और प्राथमिक विद्यालय ताहिरपुर अपने-अपने संसाधनों, अनुशासन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दम पर आदर्श बन चुके हैं। कंपोजिट विद्यालय भरतपुर में कक्षा-कक्ष रूपांतरण, कंप्यूटर व प्रिंटर युक्त ऑफिस, स्मार्ट बोर्ड, टीवी, ब्लूटूथ, प्रोजेक्टर, माइक-स्पीकर, मॉर्निंग असेम्बली माइक, सीसीटीवी कैमरा व वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक कक्षा डेस्क-बेंच से सुसज्जित है तथा सौंदर्यपूर्ण वातावरण बच्चों को आकर्षित करता है। विद्यालय को 19 पैरामीटर पर संतृप्त घोषित किया गया है। यहां निःशुल्क शिक्षा के साथ कंप्यूटर शिक्षा व वीरांगना लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। शून्य निवेश से बनी लाइब्रेरी, डीलएमएस और साफ-सुथरे शौचालय इसकी विशेषता हैं। विद्यालय की इंचार्ज हेड टीचर संगीता सिंह ने बताया कि इन सभी कार्यों की सफलता सहायक अध्यापक राजू सिंह के सहयोग से संभव हुई है। वहीं, प्राथमिक विद्यालय ताहिरपुर आधुनिक संसाधनों से लैस होकर गुणवत्तापरक शिक्षा का आदर्श बन चुका है। यहां सभी कक्षाओं में स्मार्ट टीवी व टीएलएम उपलब्ध हैं। 7 जून 2022 को जनपद का पहला डिस्कवरी लैब यहीं स्थापित हुआ, जिसमें विज्ञान के 150 से अधिक उपकरण हैं। प्रधानाध्यापक डॉ. अमित सिंह के नेतृत्व में विद्यालय 2018 में 63 बच्चों से बढ़कर आज 262 बच्चों तक पहुँच गया है। एसी युक्त कार्यालय, आरओ व वाटरकूलर से शुद्ध पेयजल, सोलर पैनल आधारित विद्युत आपूर्ति और अत्याधुनिक शौचालय जैसी सुविधाओं के चलते यह विद्यालय निजी स्कूलों को भी चुनौती दे रहा है। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने दोनों विद्यालयों की सराहना करते हुए कहा कि भरतपुर और ताहिरपुर विद्यालय शिक्षा व संसाधनों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।

छात्राएं आगे बढ़कर करें समस्याओं का सामना: एसपी

साखोपार,कुशीनगर।

गुरुवार को किसान इंटर कॉलेज साखोपार में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे जनपद में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के नेतृत्व में मिशन शक्ति कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों,विशेषकर छात्राओं को आत्म सुरक्षा और आत्म सम्मान की रक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान जिन छात्राओं ने समाज या विद्यालय के छात्रों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई,उन सभी को पकड़ कर पूरे विद्यालय के सामने कार्यवाई की गई। ऐसे लगभग 8 मामले पुलिस अधीक्षक के सामने उनकी टीम ने प्रस्तुत किया। साथ ही छात्राओं को आगे आकर इस समस्या से लड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक ने प्रेरित किया। इस अवसर पर

किसान इंटर कॉलेज साखोपार में आयोजित हुआ मिशन शक्ति कार्यक्रम

विद्यालय में पुलिस की तरफ से नियमित शिकायत पेटिका लगाई गई । जिन छात्राओं को मौखिक शिकायत करने में किसी प्रकार की समस्या महसूस हो तो वे पेटिका में अपनी बात लिखकर डाल सकती हैं,जिसे समय समय पर महिला पुलिस अधिकारी आकर ले जाएंगी। इसी के साथ छात्राओं को ऑपरेशन मजनू के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन व्यायाम शिक्षक नवनीत लाल ने किया। अतिथियों का स्वागत और धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य डा. अखिलेश सिंह ने किया।इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक कनिष्क कुमार सिंह, पवन कुमार पाण्डेय, गिरिजेश कुमार सिंह, सोनभद्र सिंह, ज्ञान सागर,रणधीर कुमार चतुर्वेदी, यशवंत सिंह, मकसूदन,शैलेश कुमार, आलमगीर आलम, ओम प्रकाश पाण्डेय, साधना सिंह, प्रशांत कुमार सिंह,दीपमाला मिश्रा, सतीश यादव, सत्येंद्र कुमार वर्मा, आयुषी सिंह, गरिमा मिश्रा,प्रेम कुमार शर्मा, कन्हैया कुमार,पंकज कुमार, लाल बाबू यादव, शोभा गौतम, मंतोष कुमार, रवि,सच्चिदानंद यादव और पुलिस टीम से कसया क्षेत्राधिकारी कुंदन सिंह,महिला थाना की एसएचओ सुमन सिंह,अमित शर्मा, लाल बहादुर शर्मा,रोहित सिंह,आदर्श मिश्रा, आरक्षी सुमन सौरभ, शिवानी दुबे, शैलजा तिवारी, अंतिमा यादव, प्रियंका तिवारी आदि उपस्थित रहे।

परिषदीय विद्यालय की छात्रा का स्पोर्ट्स हॉस्टल में हुआ चयन

रामकोला,कुशीनगर। रामकोला विकासखंड के कंपोजिट विद्यालय पकड़ी बांगर की एक छात्र ने आवासीय क्रीड़ा छात्रावास हेतु हैंडबॉल खेल में चयनित होकर जिले का मान बढ़ाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपोजिट विद्यालय पकड़ी बांगर की कक्षा 7 की छात्रा सौम्या पांडेय का चयन हैंडबॉल खेल में स्पोर्ट्स हॉस्टल अयोध्या के लिए हो गया है। अब यह छात्रा स्पोर्ट्स हॉस्टल में उत्तरप्रदेश खेल निदेशालय की देख-रेख में आगे की शिक्षा एवं अपने खेल में विशेषज्ञता निःशुल्क प्राप्त करेगी। विदित हो कि कंपोजिट विद्यालय पकड़ी बांगर से पिछले 3 साल में तीन बच्चों का चयन स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए हो चुका है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस छात्रा की सफलता पर बीएसए डॉ. राम जियावन मौर्य,

बी.ई.ओ राजेश कुमार,जिला क्रीड़ा अधिकारी रवि कुमार निषाद, प्रधानाध्यापिका सुनीता सिंह,जिला व्यायाम शिक्षक अनिल मिश्रा, क्षेत्रीय व्यायाम शिक्षक डॉ.शंकर दयाल पाठक, शिक्षक चंद्रशेखर चांद सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ और और समाजसेवी ज्ञानवर्धन गोविंद राव ने बधाई दी है।

सीलिंग पट्टेदारों ने तहसीलदार कसया को सौंपा ज्ञापन

कसया, कुशीनगर । कसया तहसील पर कुड़वा उर्फ़ दिलीपनगर, पिपरा, सखवनिया और मैनपुर के 200 सीलिंग भूमि पट्टेदारों की असंगठित मजदूर यूनियन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में जमावाड़ा हुआ। पट्टेदारों ने कुड़वा में सीलिंग की भूमि पर वितरित पट्टे की भूमि पर सीलिंग होल्डर के द्वारा कराये जा वृक्षारोपण और केला रोपड़ तथा पिपरा प्रेमनगर में सीलिंग होल्डर द्वारा सीलिंग भूमि पट्टे को बाहरी लोगों को बेचने, खनन कराने और अवैध मकान निर्माण कराने में सहयोग करने तथा सखवनिया में पट्टेदारों को बेदखल करने के विरुद्ध कार्यवाही के लिए उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार कसया को ज्ञापन सौंप त्वरित कार्यवाही की मांग किये तथा यह भी चेताये की त्वरित कार्यवाही नहीं होने पर धरना और रैली करने को बाध्य होंगे। मैनपुर के टोला डेलिहवा में आवासीय भूमि की पट्टा के लिए मुसहर महिलाओं ने ज्ञापन सौप कार्यवाही की मांग किये। धर्मवीर सिंह तहसीलदार कसया द्वारा ज्ञापन लेकर एक सप्ताह के अंदर सीलिंग भूमि और पट्टे की जाँच कराकर त्वरित कार्यवाही कर सीलिंग होल्डर द्वारा किये जा रहे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने का आश्वासन दिए। मैनपुर में आवासीय भूमि की जाँच कराकर भूमि उपलब्ध होने पर जरूरतमंद परिवारों को आवासीय पट्टा वितरण करने का आश्वासन दिए। इस अवसर पर असंगठित मजदूर यूनियन के अक्षयबर पैसावन, मौकल चौधरी प्रियंका रामबाहल सिंह और कामरेड अयोध्याला श्रीवास्तव जिला मंत्री मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कामरेड बीपी गुप्ता, कामरेड इद्रेश, कामरेड गेंदा सिंह, कैलास गिरी खेत मजदूर यूनियन के साथ शंकरलाल श्रीवास्तव, त्रिवेंद्रम शर्मा, रघुनाथ, वंशी, हुसैन, पृथि, प्रभावती, गुलाबी, ओमप्रकाश, परसुराम, विजुली प्रसाद, रामलाल, लक्ष्मन शर्मा, परमहंस चौहान, बाबुलाल, शिव चौहान, इशरवारी, विदावती,फुला रम्भा, आद्या, दीपक, सुमंत, संदीप पटेल, वकील आदि सैकड़े पट्टेदार उपस्थित।

गंडक नदी पर बनेगा 4.5 किमी लंबा पुल

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर ।

कुशीनगर के खड्डा में गंडक नदी के मैसहा घाट पर पक्का पुल बनने की राह अब आसान होती नजर आरही है। लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग रही इसपुल परियोजना को लेकर जिला प्रशासन,सेतु निगम, बाढ़ खंड और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने तकनीकी बिंदुओं पर गहराई से चर्चा करते हुए संभावित डिजाइन और पुल की लंबाई को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान सेतु निगम के डायरेक्टर मिथिलेश कुमार, अधिशासी अभियंता राजेश निगम, सहायकअभियंता आभिनव मिश्रा, अधिशासी अभियंता पवन सिंह और विवेक कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने पहले गंडक नदी की धारा औरआसपास के भौगोलिक हालात का जायजा लिया।इसके बाद प्रस्तावित पुल की लंबाई लगभग 4.5किलोमीटर तय की गई, जो मुख्य सड़क से जुड़कर दियारा क्षेत्र में बसे गांवों के लिए जीवन रेखा साबित होगी।अधिकारियों ने माना कि गंडक नदी की बदलती धाराऔर बाढ़ के दौरान बनने वाले दबाव को ध्यान में रखते हुए पुल का निर्माण चुनौती पूर्ण होगा, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से यह पूरी तरह संभव है। इसके लिए विस्तृतपरियोजना रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में तेजी लाने का निर्णय लिया गया।निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रितहो गई। ग्रामीणों ने पुल निर्माण की योजना को लेकरअपनी खुशी और उम्मीद जताई। उनका कहना था किपक्का पुल बनने से खड्डा और आसपास के क्षेत्रों मेंआवागमन सुगम होगा। अभी लोगों को बरसात औरबाढ़ के दिनों में नाव का सहारा लेना पड़ता है, जिससेशिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहंच बाधित रहती है।

पुल बन जाने से न केवल बच्चों की पढ़ाई आसान होगीबल्कि व्यापार और दैनिक जीवन भी सहज होगा।ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल से दियारा क्षेत्र में बसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच आसान होगी, मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में सुविधा मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आपात कालीन स्थिति में भी लोगों कोअब नाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय ने कहा कि यह पुलइस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार बनेगा। दशकों से लोग इस परियोजना की मांग कर रहेथे। अगर यह योजना धरातल पर उतरती है, तो गंडकपार का पूरा इलाका तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है नारायणी नदी परपक्का पुल बनवाना जब से मैं चुनाव जीता हु तब सेरेता वासियों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हु कि हरसुविधा रेता वासियों के लिए व्यवस्था कर सकू ,पुल निर्माण की खबर से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।लोगों का कहना है कि यह केवल कंक्रीट का ढांचा नहींहोगा, बल्कि दियारा और मुख्य भू-भाग को जोड़ने वालीजीवन रेखा साबित होगा।रेता क्षेत्र के निवासी राकेश गुप्ता ने कहा कि पक्का पुलबन जाने से आवागमन की सुविधा आसान हो जाएगी अपने मुख्यालय से जुड़ने के लिए बिहार होकर आनापड़ता है ,पुल बनने के बाद बहुत आसानी और कम दूरी तय करनी पड़ेगी।

हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई से आईं आपदाएं, कोर्ट की सुप्रीम टिप्पणी

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बाढ़ और बारिश से संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बारिश और बाढ़ पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि पहाड़ियों में पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी में पहाड़ियों से बहकर आई बड़ी संख्या में लकड़ियों के लट्ठे के वीडियो का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ पर संज्ञान लिया। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनडीएमए और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई के कारण आपदाएं आई हैं। कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें पेड़ों की अवैध कटाई को ऐसी आपदाओं का एक प्रमुख कारण बताया गया था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और पंजाब की सरकारों को भी नोटिस जारी किए। पीठ ने अनामिका राणा की ओर से दायर याचिका को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है। मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी बहकर आई। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। इसलिए, प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। दो सप्ताह में जवाब दें। पीठ ने याचिकाकर्ता अनामिका राणा की ओर से पेश अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ और शुभम उपाध्याय को केंद्रीय एजेंसी को नोटिस और याचिका की प्रति देने की अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कृपया इस पर ध्यान दें। यह एक गंभीर मुद्दा प्रतीत होता है। बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे इधर-उधर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यह पेड़ों की अवैध कटाई की ओर इशारा करता है। हमने पंजाब की तस्वीरें देखी हैं। पूरे खेत और फसलें जलमग्न हो गई हैं। विकास को राहत उपायों के साथ संतुलित करना होगा। विधि अधिकारी ने कहा, हमने प्रकृति के साथ इतना हस्तक्षेप किया है कि प्रकृति अब हमें जवाब दे रही है। मैं आज ही पर्यावरण मंत्रालय के सचिव से बात करूंगा और वह राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे। मेहता ने कहा कि ऐसी स्थितियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। वकील आकाश वशिष्ठ के माध्यम से दायर याचिका में भूस्खलन और अचानक बाढ़ के कारणों की कार्ययोजना बनाने और एसआईटी जांच कराने के साथ-साथ ऐसी आपदाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के उपाय करने की मांग की गई है।

बाढ़ से दिल्ली का हाल बेहाल

सचिवालय, रिंगरोड, सिविल लाइंस सहित इन इलाकों में घुसा पानी, गाड़ियां आधी डूबीं

नई दिल्ली।

दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. गुरुवार (4 सितंबर) की सुबह पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर था. उफनती यमुना का पानी आस-पास के इलाकों में लगातार भर रहा है. निगमबोध घाट की दीवार टूट गई है. सचिवालय में पानी घुस गया है, जहां मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और प्रमुख नौकरशाहों के कार्यालय हैं. इसके अलावा, वजीराबाद में लोगों ने कहा कि वे बाढ़ से काफी परेशान हो गए हैं. वोट लेने सब आ जाते हैं, लेकिन जरूरत के समय कोई नहीं आता.

मोनेस्ट्री मार्केट, सिविल लाइंस और गीता कॉलोनी में भी पानी

मोनेस्ट्री मार्केट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है. रिंग रोड पर भी पानी भर गया है. गाड़ियां आधा डूब के चल रही हैं और सड़कों पर लंबा जाम है. सिविल लाइंस में स्वामी नारायण मंदिर में पानी पहुंच गया है. मंदिर परिसर में पानी भर जाने के कारण लोग छतों पर चले गए हैं. गीता कॉलोनी में यमुना में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. श्मशान घाट भी अछूता नहीं रहा है.

राहत शिविर भी जलमग्न

वासुदेव घाट के आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है. मयूर विहार फेज-1 जैसे कुछ निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर गया है. यहां तक कि वहां बने राहत शिविर भी जलमग्न हो गए हैं. मोनेस्ट्री मार्केट के साथ यमुना बाजार जैसे इलाके अब भी जलमग्न हैं. निवासियों को उम्मीद है कि पानी कम हो जाएगा और सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी. कश्मीरी गेट के पास श्री मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर तक भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है. एक श्रद्धालु ने कहा, ''हर साल जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो इससे भगवान हनुमान का स्नान होता है. यह पवित्र जल है. हम इसका सम्मान करते हैं.''

श्मशान घाट में बड़ा नुकसान

गीता कॉलोनी श्मशान घाट के प्रमुख संजय शर्मा ने दावा किया, ''2023 में श्मशान घाट में पानी घुस गया था और आज फिर से लगभग 10 फुट तक पानी भर गया है. नुकसान बहुत बड़ा है क्योंकि बाहर रखी सारी लकड़ियां बर्बाद हो गई हैं. हमें प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है.'' क्योंकि कुछ श्मशान घाट पहले ही बंद कर दिए गए हैं, इसलिए लोग दूर-दूर से यहां आ रहे हैं. यमुना की बाढ़ का असर मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में भी नजर आ रहा है. मथुरा में महावन तहसील और छाता तहसील के यमुना किनारे बसे गांव, खेतों और लिंक रोड पर पानी पहुंचा है जिससे गांव की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है. अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं.

बाढ़ग्रस्त पंजाब में ग्राउंड जीरो पर शिवराज, किसानों का दर्द सुना, मदद का किया वादा

नई दिल्ली।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पंजाब के अमृतसर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आज अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने इलाके में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनीं। मंत्री चौहान ने लगातार भारी बारिश के कारण जलभराव से क्षतिग्रस्त फसलों का भी निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री चौहान आज पंजाब के अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद चौहान देर शाम अमृतसर में अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए लौटेंगे। शिवराज ने कहा कि आज पंजाब संकट में है। जलप्रलय की स्थिति है। फसलें डूबी हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। हम गांवों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे, ग्रामीणों से संवाद करेंगे। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब की जनता के साथ खड़ी है। बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, मैं कल (4 सितंबर) पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा हूं।

मैं अपने किसान भाइयों और बहनों, लोगों से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। राज्य सरकार के साथ मिलकर वह लोगों के लिए हर संभव कदम उठाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से पंजाब जाकर वहां के हालात देखूंगा। मैं लोगों और किसानों से चर्चा करूंगा। नुकसान की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, चौहान ने कहा, सीमावर्ती जिलों में बाढ़ की स्थिति है। जनजीवन अस्त-व्यस्त है। जनता संकट में है। किसान संकट में हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें जलमग्न हैं। संकट की इस घड़ी में, केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, लोगों के साथ खड़े हैं।

> **शिवराज ने कहा कि आज पंजाब संकट में है। जलप्रलय की स्थिति है। फसलें डूबी हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। हम गांवों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे, ग्रामीणों से संवाद करेंगे। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब की जनता के साथ खड़ी है।**

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश हुई, और मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज और बिजली गिरने की नई चेतावनी जारी की। आने वाले दिनों में पंजाब में मानसून की गतिविधियां थोड़ी कमजोर होने की संभावना है, जबकि उत्तर और दक्षिण हरियाणा तथा चंडीगढ़ के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है।

कुकी समूह के साथ राज्य और केंद्र की बड़ी डील, एनएच-2 खोलने पर सहमति

नई दिल्ली। केंद्र और मणिपुर सरकार ने गुरुवार (4 सितंबर 2025) को कुकी-जो काउंसिल (केजेडसी) के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सभी पक्ष राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए नेशनल हाईवे-2 को खोलने पर सहमत हुए. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों और केजेडसी के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच पिछले कुछ दिनों में कई बैठकें हुईं. तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की. गृह मंत्रालय ने बताया कि केजेडसी ने राज्य के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले एनएच-2 पर शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से तैनात सुरक्षाबलों के साथ सहयोग का आश्वासन दिया है. मणिपुर को नागालैंड और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली एनएच-2 मई 2023 से राज्य में भड़के जातीय तनाव के कारण बंद हो गई थी. नेशनल हाईवे को फिर से खोलने को हिंसा प्रभावित मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है. इंफाल और नई दिल्ली, दोनों जगहों के अधिकारियों का मानना है कि आवश्यक सामानों की पहुंच आसान होने से विस्थापित परिवारों और राहत शिविरों में रह रहे नागरिकों की मुश्किलें कम होंगी. गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार को नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी. इसमें तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की.

पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी का बवाल, एनडीए का बिहार बंद; राहुल- तेजस्वी से माफी की मांग

पटना।

दरभंगा में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में एनडीए ने बंद का आह्वान किया है। भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) सहित एनडीए के घटक दलों के नेता सुबह से ही सड़कों पर हैं और विभिन्न स्थानों पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद का असर पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, शिवहर और भोजपुर समेत सभी जिलों में देखा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कहीं जलाए टायर तो कहीं सड़कों पर बैठकर नारेबाजी की गई। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई। आज इसके खिलाफ एनडीए ने पांच घंटे का बिहार बंद का आह्वान किया है। हम इस बंद को सफल बना रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश से माफी मांगें। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बहुत शर्मनाक मामला है। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माता को गालियां दी गईं। अगर हमारा दूर का कार्यकर्ता भी ऐसा करता तो हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बिहार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए, मंटू ने कहा कि प्रधानमंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे बिहार के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा, जो कोई भी उनके या उनकी मां के बारे में गलत बोलेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मंटू ने आगे कहा, बिहार बंद उन दूसरी मानसिकता के लोगों के लिए है जो इन सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं; विपक्ष के लोग सही-गलत को बढ़ावा दे रहे हैं; बिहार की जनता उन्हें जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए द्वारा आज 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया है। राजद-कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया। उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का आह्वान किया गया है...जब मेरे परिवार को राजद नेता तेजस्वी यादव के सामने गालियां दी गई थीं उस समय भी इन लोगों ने मौन धारण कर लिया था। लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने इनको जवाब देना का काम किया था, इस बार विधानसभा चुनाव में भी जनता इनको जवाब देगी।

बंगाल विधानसभा में बीजेपी-टीएमसी विधायकों के बीच हुई हाथापाई

कोलकाता। बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में अभूतपूर्व हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे ही प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ी हुईं विपक्षी भाजपा के विधायकों ने सीटों से खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी।

पांच भाजपा विधायक निलंबित

लगातार नारेबाजी व सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) बिमान बनर्जी ने पांच भाजपा विधायकों- मुख्य सचेतक डॉ. शंकर घोष, अग्निमित्रा पाल, मिहिर गोस्वामी, अशोक डिंडा व बंकिम घोष को आज के लिए सदन की शेष कार्यवाही से निलंबित कर दिया। डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सदन में दोनों तरफ से लगातार नारेबाजी व हंगामा चलता रहा। मुख्यमंत्री के पूरे भाषण के दौरान भाजपा विधायकों ने जबरदस्त नारेबाजी की। इस दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने भी भाजपा को चोर- चोर बताते हुए नारेबाजी की। हंगामे की शुरुआत दोपहर 1.50 बजे तब हुई जब मुख्यमंत्री जैसे ही प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ी हुईं, भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव पर हमारे सभी वक्ताओं को स्पीकर ने बोलने नहीं दिया। इस दौरान भाजपा विधायकों और मार्शलों के बीच जमकर हाथापाई हुई। उन्हें बाहर निकालने की कोशिश के बीच भाजपा के अन्य विधायक शंकर घोष के इर्द-गिर्द जुट गए, जिससे दोनों तरफ से खूब खींचतान चली और इसी बीच घोष नीचे फ्लोर पर गिर पड़े। इससे माहौल और भी गरम हो गया। काफी मशक्कत के बाद मार्शलों ने शंकर घोष को आखिरकार जबरन खींच के सदन से बाहर निकाला।

ममता ने कहा- भाजपा बांग्ला व देश विरोधी है

वहीं, सदन में भारी शोरगुल के बीच ममता ने अपने भाषण के दौरान भाजपा पर तीखा हमला बोला। ममता ने कहा कि भाजपा बांग्ला भाषा व बंगाल से नफरत करती है। भाजपा को उन्होंने बांग्ला व देश विरोधी तक बताया। ममता ने भाजपा को चोर, डकैतों का दल बताया। कहा कि भाजपा सबसे बड़ा चोर व डकैतों का दल है। नाथूराम गोडसे का दल है भाजपा। पूरे देश में भाजपा अत्याचार कर रही है। बंगाल में भी उत्पीड़न कर रही है, मेरी बात को लोग सुन नहीं सके ये भाजपा की साजिश है। बांग्ला भाषा को अपमानित करने वाली पार्टी का नाम भाजपा है। भाजपा बंगाल को पराधीन करना चाहती है। मैं बांग्ला भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी।

ममता ने मोदी चोर के लगाए नारे

ममता ने सदन में भाजपा चोर, मोदी चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लगाए। ममता ने कहा कि देश से अब भाजपा की विदाई का घंटा बजा चुका है। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं भाजपा को धक्का देकर जीरो कर दूंगी। ममता ने कहा कि भाजपा का आजादी के आंदोलन से कोई सरोकार नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अंग्रेजों के साथ साजिश कर उसने (भाजपा) देश का विभाजन करा दिया और देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लेकर चला गया।

गुंडा टैक्स सपा सरकार का संस्कार था: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब ईवीएम से हुए चुनाव में जब विपक्ष जीतता है, तो उसे पुरुषार्थ लगता है, लेकिन भाजपा जीते तो कहते हैं कि बेईमानी हुई है। उन्होंने कहा कि ईवीएम और वोटर लिस्ट पर सवाल उठाना केवल बहानेबाजी है। विपक्ष की यह मानसिकता लोकतंत्र को कमजोर करती है। मुख्यमंत्री गुरुवार को गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) में 2251 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वांचल में विकास और निवेश की जो नींव रखी है, उसका लाभ अब जमीन पर दिख रहा है। सीएम योगी ने आइएनडीआइए गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह भारत को फिर गुलामी की ओर ढकेलना चाहता है। उन्होंने कहा, विकसित भारत की राह में यही सबसे बड़ा बैरियर है, जिसे भारत का किसान, मातृशक्ति और युवा उखाड़ फेंकेंगे। मुख्यमंत्री ने सख्त शब्दों में कहा कि अब गीडा हो या प्रदेश का कोई और हिस्सा, कोई भी सपाई गुंडा टैक्स नहीं वसूल सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा, उसे चौराहे पर यमराज मिलेंगे। सीएम योगी ने कांग्रेस और राजद नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा, दुर्गा सप्तशती में कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। 140 करोड़ देशवासी इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे।

> **ईवीएम से विपक्ष जीता तो पुरुषार्थ, भाजपा जीते तो बेईमानी, गोरखपुर से बिहार चुनाव साध रहे सीएम योगी**

गीडा में निवेश का बड़ा दौर, 15 हजार को मिलेगा रोजगार

सीएम ने कहा कि पहले पूर्वांचल का युवा रोजगार के लिए देश-दुनिया में भटकता था। अब उसे अपने ही जिले में काम मिल रहा है। गीडा में गोरखपुर के साथ-साथ अयोध्या, कुशीनगर, आजमगढ़ और देवरिया के युवाओं को भी काम मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गीडा में 2251 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई परियोजनाओं से करीब 15 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसमें 700 करोड़ का कोका कोला प्लांट भी शामिल है, जिससे 1500 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा प्लास्टिक पार्क में 120 करोड़ के निवेश से उद्योग स्थापित किए गए हैं।

तीन नई यूनिटों का लोकार्पण हुआ। 281 करोड़ की आधारभूत संरचना परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया गया।

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा एक्टिव: सभी सांसदों को 6 सितंबर तक दिल्ली पहुंचने का निर्देश

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी सांसदों को एक पत्र जारी कर 6 सितंबर तक दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी पार्टी सांसदों को 6 सितंबर को शाम 7 बजे अपने आवास पर रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया है। 7 सितंबर को सांसदों को सुबह 9 बजे से देर शाम तक आयोजित पार्टी कार्यशाला में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। यह कार्यशाला 8 सितंबर को संसद परिसर स्थित जीएमसी बालयोगी सभागार में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। उसी शाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे। 9 सितंबर को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करेंगे।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंच तैयार है, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। विपक्ष को सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद के लिए मनाने की सरकार की कोशिशें नाकाम हो गई हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक बताया गया है। वर्तमान में, संसद के दोनों सदनों को मिलाकर सदस्यों की संख्या 787 है। भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को कम से कम 394 मतों की आवश्यकता होती है।

मराठा आरक्षण को लेकर संजय राउत ने छगन भुजबल पर साधा निशाना

नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर भुजबल को लगता है कि मराठा आरक्षण के फैसले से ओबीसी समुदाय के साथ

नाइंसाफी हुई है, तो उन्हें अपनी आत्म-सम्मान की खातिर और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण आंदोलन को हवा देकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की। राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ओबीसी समुदाय के बड़े नेता भुजबल ने खुद माना है कि उनके समुदाय के साथ नाइंसाफी हुई। इसके बावजूद वह उस मुख्यमंत्री के अधीन काम कर रहे हैं, जिनके फैसले से यह नाइंसाफी हुई। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर भुजबल को अपने समुदाय की इतनी फिक्र है, तो उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। छगन भुजबल ने बुधवार को मराठा आरक्षण पर सरकार के ताजा फैसले से नाराजगी जताई थी और कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लिया।

बिहार चुनाव : नवंबर में 3 चरणों में मतदान संभव, त्योहारों के बीच तैयारी

नई दिल्ली। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि, माना जा रहा है कि इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं, चुनाव आयोग के सूत्रों बताया कि नई बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। मतदान तीन चरणों में होने की उम्मीद है, और अंतिम कार्यक्रम दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के आसपास निर्धारित किया जा रहा है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त होगा और चुनाव आयोग को उस तिथि से

पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पिछली परंपरा के अनुरूप, बिहार में भी कई चरणों में मतदान होगा। 2020 के चुनाव तीन चरणों में हुए थे - 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, 3 नवंबर को 94 सीटों पर और 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ था। नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे। 2015 में, मतदान पांच चरणों में हुआ था। इस साल की लड़ाई एक बार फिर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के बीच होगी। भाजपा, जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से मिलकर बना एनडीए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक और कार्यकाल की उम्मीद कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाला विपक्षी खेमा, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद कर रहा है। 243 सदस्यीय विधानसभा में, एनडीए के पास वर्तमान में 131 सदस्यों के साथ बहुमत है।